additional 1% rebate (over and above 4% subsidy announced) for PFC loans under Accelerated Generation Plan Scheme. The Government had set up a one member committee under Shri S.J. Coelho to study private sector participation in distribution. The various model of privatisation of distribution as recommended by the committee have been recommended to the State. The Government also enacted the Electricity Laws (Amendment) Act, 1998 on 10th August, 1998 for making transmission an independent activity and encouraging private investment in transmission sector. A conference of Chief Ministers is scheduled for 18/12/1998 to discuss the status of reforms in various States.

(c) Details of present status of the implementation of reform package/structural reforms SEB-wise are given in Annexure. [*See Appendix 185, Annexure No. 46]*

(d) Details of the schemes drawn up by PFC and other financial institutions for structural reforms of SEB and upgradation of infrastructure network are given in Annexure.

[*See Appendix 185, Annexure No. 46]*

Mega Hydro Projects

1815. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) what is the present installed capacity of the country's hydro sector;

(b) whether the Central Electricity Authority has identified some mega hydro projects for execution in the next 15 years by the National Hydro-electric Corporation;

(c) if so, the details thereof, state-wise; and

(d) the criteria adopted for the selection of these projects?

THE MINISTER OF POWER (SHRI P.R. KUMARAMANGALAM): (a) The present installed capacity of the hydro sector in the country is 21,891.08 Mega Watts (MW). Hydro plants account for 24.80 per cent of the total installed capacity.

(b) and (c) In September, 1998, the Central Electricity Authority (CEA) identified hydro projects which could be considered for execution by National Hydro-electric Power Corporation (NHPC) after obtaining the necessary clearances in the next fifteen years. The State-wise details of the projects identified by CEA for execution by NHPC are given in the enclosed Statement. (*See* below)

(d) The broad criteria for identification of the projects are:

(i) The schemes should be of large capacity.

(ii) Projects located in the vicinity of projects being developed or already developed by NHPC were considered for execution so that infrastructure already established could be utilised.

Statement

State-wise details of projects identified by CEA for execution by NHPC

Sl. No.	Name of the Scheme	State	Installed Capacity (MW)
1.	Sawalkot	J&K	600
2.	Kol Dam	H.P.	800
3.	Parbati St. II	H.P.	800
4.	Kishau	U.P.	600
5.	Kadwan	Bihar	450
6.	Teesta St. III	Sikkim	1200

Sl. No.	Name of the Scheme	State	Installed Capacity (MW)
7.	Teesta St. II	Sikkim	373
8.	Teesta St. IV	Sikkim	495
9.	Tipaimukh	Manipur	750
10.	Dihang	Arunachal Pradesh	13400
11.	Subansiri	Arunachal Pradesh	7300
12.	Demwe	Arunachal Pradesh	520
13.	Lohit	Arunachal Pradesh	3000
14.	Kimi	Arunachal Pradesh	1100
15.	Debang Dam	Arunachal Pradesh	1000
16.	Bhopalapatnam	M.P.	1000
17.	Pimpalgaon	Maharashtra	600
18.	Mananthawadi	Kerala	240
19.	Hoganekkal	Tamil Nadu	850

विद्युत परियोजनाओं की निर्माण लागत

1816. **श्री कपिल सिब्बल:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 जून, 1998 के "दि इकोनोमिक टाइम्स" में "बाबज मेस्ड अप रिफोर्मस सेज जी०वी०आर०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बिजली परियोजनाओं के निर्माण की लागत 2.2 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट तक नीलामी के रूप में आंकी जाती है जबकि भारत में यह लागत 4 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट या इससे अधिक आंकी जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में परियोजना निर्माण लागत अधिक होने के क्या कारण है?

विद्युत मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम): (क) से (ग) विद्युत संयंत्र की लागत उसकी किस्म, क्षमता, स्थल संबंधी स्थितियों, ईंधन की किस्म संयंत्र का विस्तृत कार्यक्षेत्र और वित्त पोषण के स्वरूप पर निर्भर करता है। जबकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा हाल ही में स्वीकृत कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र की समग्र लागत 4.2 करोड़ रु०/मे०वा० है, तथापि, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नैफ्था आधारित संयुक्त साइकिल सयंत्र की लागत में 3.0 करोड़ रु०/मे०वा० से 3.5 करोड़ रु० तक की भिन्नता है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की जा रही लागत में शुल्क और कर तथा वित्त पोषण की उच्च लागत भी शामिल है। इसके अतिरिक्त भारतीय परिवेशी परिस्थितियों के परिणामस्वरूप उसी संयंत्र से विशेषकर गैस टर्बाइन संयंत्रों के मामले में उत्पादन कम हो जाता है। इससे भारत में विद्युत संयंत्रों की प्रति मे०वा० लागत में और अधिक वृद्धि हो जाती है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की जा रही लागत अधिष्ठापित किए गए के अनुसार संपूरित लागत है। जिसमें विद्युत संयंत्रों को निर्माण हेतु सभी सिविल कार्य और सभी अन्य बुनियादी सुविधाएं जैसे बाह्य जल प्रणाली बाह्य ईंधन प्रहस्तन प्रणाली, ईंधन भंडारण इत्यादि शामिल हैं।

उपर्युक्त सभी घटकों की अनुमति प्रदान करने के पश्चात् केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की जा रही लागत की तुलना विद्युत संयंत्रों के लिए दिए गए अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से की जा सकती है जो कि संयुक्त साइकिल संयंत्रों के मामले में 2.0—2.3/करोड़ रु०/मे०वा० है और कोयला आधारित संयंत्रों के लिए 2.6—3.5 करोड़ रु०/मे०वा० है।

Pendings Power Projects of North Eatern Region

1817. **SHRIMATI BASANTI SARMA:** Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the details of the proposals for setting up of power projects in the coun-